विचार बिन्दु

दूसरों पर शक करना कभी-कभी गुनाह हो जाता है। –कुरान

सरकारें क्यों हमारी परेशानियां बढ़ाती हैं?

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक आदेश ज़ारी करके सभी वाहनों के लिए, भले ही उनका निर्माण कभी भी हुआ हो, हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया था। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण है। वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बारे में यह व्यवस्था इस तरह काम करती है कि केंद्र सरकार यह व्यवस्था निर्धारित करने के लिए अधिकृत है और उसका अधिकार क्षेत्र इन नंबर प्लेट्स का विवरण निर्धारित करने और उनका परीक्षण करने वाले निकायों के बारे में अधिसूचना ज़ारी करने तक सीमित है। केंद्र सरकार इस बात के निर्धारण के लिए भी अधिकृत है कि नई तरह की नंबर प्लेट्स कब से प्रभावी होंगी। इसके बाद राज्य सरकारों की भूमिका शुरू होती है। उनका दायित्व है कि वे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं को लागू करें। राज्य सरकारें ही इस बात के लिए भी अधिकृत है कि वे किसी या किन्हीं वेण्डर्स को इन नंबर प्लेट्स के बनाने और लगाने के लिए चुनें।

वैसे तो हर वाहन पर नंबर प्लेट लगाई ही जाती रही है, पारंपरिक नंबर प्लेट की बजाय यह तथाकथित हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार के इस वक्तव्य में मिलता है कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और वाहनों की चोरी को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। कहा गया है कि इन नंबर प्लेट्स को इस तरह से बनाया गया है कि न तो एक बार लगाने के बाद इन्हें बग़ैर तोड़े वाहन से हटाया जा सकता है और न ही इनकी नकल की जा सकती है या इनमें किसी तरह का कोई बदलाव किया जा सकता है। इन नंबर प्लेट्स पर एक होलोग्राम भी होता है जो इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्य के लिए अधिकृत वेण्डर्स की सूची भी ज़ारी कर दी थी। जैसा हमारे देश में आम है, आम जन से अनुरोध किया गया कि वे एक निश्चित तिथि तक अपने वाहनों पर ये नई किस्म की हाई सिक्यूरिटी वाली नंबर प्लेट लगवा लें अन्यथा उन्हें पांच से दस हज़ार रुपये तक का भारी अर्थ दण्ड झेलना पड़ेगा।

प्रारम्भ में पूरे देश में कुल 18 कंपनियों आदि को विभिन्न राज्यों में इस तरह की नंबर प्लेट्स बनाने और लगाने के लिए अधिकृत किया गया। हमारे राज्य राजस्थान के लिए इस तरह की नंबर प्लेट्स लगाने के लिए एक कम्पनी सियाम को अधिकृत किया गया था। सियाम अर्थात सोसाइटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स, जो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। लोगों ने इन नंबर प्लेट्स के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, और मंथर गति से यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई। सियाम ने आवेदन करने वालों को सूचित भी करना शुरू कर दिया कि वह उनके वाहन पर कब तक नंबर प्लेट लगा देगी। तभी अचानक हमारी राजस्थान सरकार जागी। सरकार ने एक बयान ज़ारी कर कहा कि राज्य में कुल तीस लाख वाहनों पर नंबर प्लेट लगाई जानी थी, लेकिन आठ माह की अवधि में केवल 4.44 लाख वाहनों पर ही नंबर प्लेट्स लग सकी है, जबकि सोलह लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन कर रखा है। सरकार ने कहा कि अगर यही गति रही तो सारे आवेदकों के वाहनों पर नंबर प्लेट्स लगाने में कम से कम तीन साल लग जाएंगे।

सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पांच दिन में सियाम पोर्टल बंद करने का निर्देश दे दिया और कम्पनी को कहा कि वह पांच दिन में आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि रिफंड कर दे। सियाम का पोर्टल बंद करके सरकार अपना पोर्टल बनाना चाहती है। जो लोग सरकार के काम करने की प्रक्रिया और गति से परिचित हैं वे भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार का पोर्टल कब बनेगा और वह किस दक्षता से काम करेगा। एक तरफ सरकार का यह कदम है तो दूसरी तरफ राज्य के ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं जो सरकार के इस कदम से नाखुश हैं। उनका कहना है कि सियाम पोर्टल राजस्थान परिवहन विभाग को निःशुल्क सेवा दे रहा था और राज्य में इन नंबर प्लेट्स की दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम थी। इतना ही नहीं इन्होंने यह भी बताया कि कम से कम छह लाख नंबर प्लेट्स बनी हुई तैयार रखी हैं लेकिन लोग उन्हें लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मतलब यह कि गति उतनी भी धीमी नहीं है, जितनी सरकार बता रही है। जिन लोगों ने सियाम को पैसा दे दिया है वे अपने पैसे की वापसी को लेकर चिंतित हैं। हर कोई जानता है कि किसी से दिया हुआ पैसा वापस लेना कितना कठिन होता है। इसके अलावा लोगों को चालान होने का डर भी सता रहा है, हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार का मन कब बदल जाए, कोई नहीं जानता।

ऐसा कोई ताला नहीं बना, जिसे खोलना चोर को न आता हो। अब यही बात देख लीजिए कि सरकार की इस व्यवस्था के बाद कितने अनधिकृत और धोखेबाज़ लोग इस धंधे में कूद पड़े हैं और जमकर जनता को चूना लगा रहे हैं। मैंने एक बड़ी ई-कॉमर्स साइट पर देखा तो पाया कि वहां खुले आम हाई सिक्यूरिटी प्लेट्स बनाई जा रही हैं, और कहना अनावश्यक है वे अनधिकृत और ग़ैर कानूनी हैं।

राजस्थान सरकार और सियाम के बीच के इस विवाद ने आम जन को अनावश्यक रूप से एक सर दर्द दे दिया है। वैसे मुझे हमेशा लगता है कि हमारी सरकारें जनता को सुविधा देने की बजाय उसकी परेशानियां बढ़ाने में ही ज़्यादा रुचि लेती हैं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इन नई तथाकथित हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट्स की, खास तौर पर पुराने वाहनों पर, अनिवार्यता का क्या औचित्य है। आपको नई व्यवस्था करनी है, नए वाहनों के लिए कर दीजिए। जिसके पास पुराना वाहन है, उसे विकल्प दे दीजिए कि अगर वह चाहे तो उस पर नई नंबर प्लेट लगवा ले अन्यथा वह पुरानी नंबर प्लेट के साथ भी अपना वाहन चला सकता है। हर परिवर्तन ऐसे ही होता है। भूतगामी प्रभाव से परिवर्तन अनावश्यक परेशानियां बढ़ाता है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन कभी होते नहीं हैं, और उनकी कमी का खामियाज़ा बेचारी जनता को भुगतना पड़ता है। बिना आगा–पीछा सोचे कुछ भी कह दिया जाता है और जनता को परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं अपनी बात कहूं। मेरे पास एक स्कूटर है, जो किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है। बरसों से वह मेरा साथ दे रहा है। अब इस नई व्यवस्था में अपेक्षा की जा रही है कि मैं उस स्कूटर को उठा कर उस राज्य में ले जाऊं और उस पर वहां से नंबर प्लेट लगवा कर लाऊं। यह कितना व्यावहारिक है? किसी ने इस तरह की समस्याओं के बारे में नहीं सोचा। ऐसी अनेक समस्याएं होंगी। किसी के पास पुराना वाहन होगा। वह जिसके नाम पर पंजीकृत होगा, वह पता नहीं कहां होगा। देश में होगा, विदेश में होगा। होगा भी या दीवार पर लटकी तस्वीर में होगा। ध्स पंद्रह बरस पुराने वाहन के कागज़ात किसी के पास होंगे ही, यह भी ज़रूरी नहीं। लगाते रहिये आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर। दलालों की जेब भरते रहिये। सरकार को आपकी परेशानियों से क्या मतलब? वह तो ऐसा कोई सिस्टम तक नहीं बनाना चाहती जहां आप अपनी समस्याओं पर सलाह ले सकें, उनके समाधान पा सकें। विश्वास न हो तो आज़मा कर देख लें। मज़ाल है जो आपकी समस्या का समाधान हो जाए! समाधान दूर आपको ठीक जवाब भी मिल जाए। और जवाब मिलना तो दूर, आप अपने भाग्य को सराहें अगर कोई आपकी बात ठीक से सुन भी ले।

राजस्थान सरकार के इस कदम पर जहां समाचार माध्यमों ने यह कयास लगाया है कि सियाम पोर्टल बंद करने की असली वजह उसके काम की धीमी गति न होकर कुछ और ही है, वहीं पूर्व परिवहन मंत्री ने भी लगभग इसी तरह की आशंका व्यक्त की है। स्वाभाविक है कि हम आम नागरिक बड़े लोगों की बड़ी बातों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उनकी ये बड़ी बातें हमारी पहले से परेशान हाल ज़िंदगी में कुछ चिंताओं की और वृद्धि करने में पूरी तरह कामयाब रहेगी, यह हमारी चिंता है।

अब भी समय है कि केंद्र और राज्य सरकार इस पूरी स्थिति का जायज़ा ले और कोई व्यावहारिक तथा विवेक सम्मत और मानवीय निर्णय लेकर इस अनावश्यक परेशानी से हमें निज़ात दिलाए। नए खरीदे जाने वाले वाहनों पर आप चाहे जैसी, कितनी ही उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेट लगवाएं, जिनके पास पुराने वाहन हैं उन्हें विकल्प दे दें कि अगर वे चाहें तो अपनी नंबर प्लेट बदलवा लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर कोई जानता है कि सारे ताले साहूकारों के लिए होते हैं। ऐसा कोई ताला नहीं बना, जिसे खोलना चोर को न आता हो। अब यही बात देख लीजिए कि सरकार की इस व्यवस्था के बाद कितने अनधिकृत और धोखेबाज़ लोग इस धंधे में कूद पड़े हैं और जमकर जनता को चूना लगा रहे हैं। मैंने एक बड़ी ई–कॉमर्स साइट पर देखा तो पाया कि वहां खुले आम हाई सिक्यूरिटी प्लेट्स बनाई जा रही हैं, और कहना अनावश्यक है वे अनधिकृत और ग़ैर कानूनी हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अनके वेण्डर्स हैं जो आपसे पैसा लेकर गायब हो रहे हैं। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि सरकार ने उनके खिलाफ़ किसी भी तरह की कोई कार्वाई की है। ऐसा करने के बारे में शायद सरकार कभी सोचती भी नहीं है। ऐसे में मेरी एक ही सलाह है। सरकार के पास जो सीमित साधन हैं उनका उपयोग उन्हें जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए करना चाहिए।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

हेरिटेज टूरिज्म मूवमेंट : देश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने और हेरिटेज होटलों के संरक्षण और पुनरुद्धार की यात्रा

देश में हेरिटेज होटल्स पर्यटन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इन हेरिटेज होटलों और प्रॉपर्टीज के संरक्षण और पुनरुद्धार के उद्देश्य के लिए इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) वर्ष 1990 में केवल 14 सदस्यों के साथ अस्तित्व में आया और सितंबर 2018 तक यह संख्या बढ़कर 193 हो गई। हेरिटेज टूरिज्म मूवमेंट का उद्देश्य हमारी ऐतिहासिक विरासतों का पुनरुद्धार, उन्हें उत्पादक स्थानों के रुप में तैयार करना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। एसोसिएशन को 1 जनवरी, 1990 को भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा विरासत वर्गीकरण को मान्यता मिली। इस प्रकार आईएचएचए का गठन 1990 में हुआ और इसे 2001 में औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया।

भारत सरकार ने जनवरी 1991 में हेरिटेज होटलों को विशिष्ट श्रेणी के रूप में मान्यता दी और हेरिटेज होटलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया– हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड। यह वर्गीकरण ट्रैवलर्स को प्रामाणिक अनुभवों की ओर मार्गदर्शन करने में सहायक रहा है, जो भारत के विविध इतिहास और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। आईएचएचए के प्रेसिडेंट एमेरिटस, जोधपुर के एचएच महाराजा गज सिंह के कुशल नेतृत्व में, एसोसिएशन में 200 से अधिक सदस्य शामिल हो गए हैं, जो सभी भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हेरिटेज होटलों का एक अनूठा नेटवर्क प्रस्तुत करता है, जो आगंतुकों को भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

आईएचएचए का प्राथमिक मिशन पूरे भारत में हेरिटेज होटलों के संरक्षण और पुनरुद्धार के माध्यम से हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये होटल्स केवल ठहरने के स्थान नहीं हैं बल्कि ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के संरक्षक हैं। इन संपत्तियों को पुनर्जीवित करके, हम पारंपरिक कला, शिल्प, संगीत और लोककथाओं को भी पुनर्जीवित करते हैं, जिससे हमारे कारीगरों और शिल्पकारों को भी अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह पहल न केवल पर्यटन के लिए बल्कि हमारे क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आईएचएचए का 11वां वार्षिक कन्वेंशन

इस वर्ष पहली बार, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) की 23वीं एनुअल जनरल मीटिंग और 11वां एनुअल कन्वेंशन राजस्थान से बाहर तमिलनाडु के तंजौर में इंडेको होटल स्वामीमलाई, कुंभकोणम में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष एजीएम और कन्वेंशन की थीम रिवाइटलाइजिंग इंडियन हेरिटेज है। हेरिटेज होटल्स मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का सार्थक उपयोग संभव हो सके। इन होटलों को बढ़ावा देने से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इसमें न केवल होटलों में प्रत्यक्ष रोजगार– जैसे आतिथ्य, प्रबंधन और रखरखाव– शामिल है, बल्कि इससे स्थानीय शिल्प, कृषि और पर्यटन सेवाओं जैसे संबंधित क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी होगा।

आईएचएचए किलों, महलों, पुराने भवनों, महलों और पारंपरिक हवेलियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है। एसोसिएशन न केवल हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी में मानक स्थापित कर रहा है, बल्कि हेरिटेज क्लासीफिक्शन गाइडलाइंस भी निर्धारित कर रहा है और साथ ही हेरिटेज होटलों की आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष भी रखता है। पिछले कई वर्षों से, आईएचएचए ने विरासत पर्यटन नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारे प्रयास राष्ट्रीय पर्यटन उद्देश्यों के अनुरूप हों।

सतत विकास और सामुदायिक सहभागिता

जैसे कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वहीं पर्यटन हमारी आर्थिक विकास का मुख्य साधन है। अब फोकस पारंपरिक लग्जरी आवासों से हटकर हेरिटेज होटलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिक मनोरम अनुभवों की ओर स्थानांतरित हो गया है। ये प्रतिष्ठान मेहमानों को स्थानीय संस्कृति और इतिहास का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्रदान करके लग्जरी को नई परिभाषा देते हैं, तथा आतिथ्य से आगे बढ़कर अनूठे और यादगार अनुभव का निर्माण करते हैं।

हेरिटेज होटल जीवंत म्यूजियम के रूप में काम करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित करने वाली वास्तुकला की उत्कृष्टता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करते हैं। वे हमारे अतीत की कहानियां बताते हैं तथा आगंतुकों को बीते युगों की परंपराओं और जीवन–शैली की झलक प्रदान करते हैं। इतिहास और आतिथ्य का यह अनूठा मिश्रण न केवल आगंतुकों के अनुभव को समृद्ध करता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आईएचएचए विरासत पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को समझता है। पर्यटन पहलों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से उनमें अपनी विरासत के प्रति स्वामित्व और गौरव की भावना बढ़ती है, जिससे सतत विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। आईएचएचए की भविष्य की योजनाओं में स्थानीय समुदायों को सहायता देने के लिए सरकारी निकायों के साथ सहयोग करना, रिस्पॉन्सिबल पर्यटन को बढ़ावा देना, तथा विरासत पर्यटन के लाभ समान रूप से वितरित हों, यह सुनिश्चित करना शामिल है।

–गज सिंह अलसीसर,
जनरल सेक्रेटरी, द इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन
(आईएचएचए)

तीन माह पहले बनाई एक करोड़ लागत की डामर की सड़क उखड़ी

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मोनिटरिंग की पोल खुली, ठेकेदार पर उठे सवाल

मांडलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ के झंझोला पंचायत में शकता जी का खेड़ा से अड़ीमलजी का खेड़ा तक मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक करोड़ की लागत से 3 माह पहले बनी डामर की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। एक करोड़ रुपये की लागत की 2 किलोमीटर तक बनी सड़क पहली बारिश में ही कई जगह से उधड़ गई और गढ्डों में तब्दील होकर कंकर मिट्टी बाहर निकल आई। जिससे सड़क पर आवागमन करने वाले ग्रामीणों और वाहन चालको में भारी रोष व्याप्त है। सड़क की डामर उखड़ने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार और पीडब्लूडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

झंझोला पंचायत के सरपंच दुर्गालाल काबरा ने बताया शकता जी का खेड़ा से अड़ीमलजी का खेड़ा तक मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक करोड़ की लागत से बनी डामर की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सड़क को गुणवत्तापूर्ण दोबारा बनाने की मांग की है। नई सड़क का डामर और कंक्रीट 3 माह में ही उखड़ कर बिखरने लगा है। जिससे आए दिन दुपहिया वाहनों से हादसे हो रहे है। नई सड़क पर गड्ढे होने से आए दिन बाइक सवार लोग फिसल कर कई बार घायल हो चुके है।

- **ग्रामीणों ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सड़क को गुणवत्तापूर्ण दोबारा बनाने की मांग की है**

झंझोला पंचायत के सरपंच दुर्गालाल काबरा का आरोप है कि सड़क निर्माण ठेकेदार ओर पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अफसरों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है,और सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने से पूरी सड़क जीर्णशीर्ण हो चुकी है।उन्होंने बताया कि मूल ठेकेदार ने थर्डपार्टी ठेकेदार से उक्त कार्य कराया हैं। ग्रामीणों ने पहली ही बारिश में उखड़ी सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है । जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान ही उन्होंने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, और पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अधिकारियों को शिकायत भी की थी। लेकिन उनकी आवाज़ को नजरअंदाज कर दिया गया।

मांडलगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता आर सी बैरवा का कहना कि मेरी जोइनिंग से पूर्व में रहे अधिकारियों के वक्त उक्त सड़क बनाई गई हैं। बारिश में सड़क के खराब होने की जानकारी मिली हैं। नई सड़क ठेकेदार की गारंटी में हैं। ठेकेदार को क्षतिग्रस्त हुई सड़क की जल्द मरम्मत करने के लिए पाबन्द किया गया है और गुणवत्ता की जाँच की जा रही हैं।

गरीबों को बांटी जाने वाली 13900 क्विंटल चीनी सात साल से प्रदेश के गोदामों में पड़ी

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश सरकारों की अनदेखी और रसद विभाग की लापरवाही के कारण गरीबों को बांटी जाने वाली करोड़ों रुपए की चीनी अब खराब चुकी है। खाद्य विभाग और सहकारी भंडारों के गोदामों में पिछले सात साल से चीनी का स्टॉक पड़ा था, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि चीनी का रंग सफेद की जगह गहरा पीला हो गया।

बीते दिनों बीकानेर के 4 गोदामों में पड़ी 613 क्विंटल चीनी स्टॉक का फूड डिपार्टमेंट से सैंपल करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आई। रिपोर्ट के अनुसार इस चीनी को अमानक माना गया, जो खाने योग्य नहीं है। बीकानेर की तरह प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 13,900 क्विंटल स्टॉक पड़ा है, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर चीनी का बाजार मूल्य जोड़ा जाए तो सरकारी गोदामों में खराब हुई चीनी की कीमत करीब 5.56 करोड़ रुपए है। अकेले बीकानेर में खराब हुई चीनी का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 24.52 लाख रुपए है।

श्रवण कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बीकानेर ने बताया कि चीनी के सैंपल लेकर उसकी जांच करवाई तो वह सब स्टैंडर्ड थी। यानी चीनी खाने योग्य नहीं है। जांच रिपोर्ट रसद विभाग को भेज दी है। आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जानी है। असल में वर्ष 2017 के बाद राजस्थान सरकार ने चीनी के वितरण में कटौती करनी शुरू कर दी। इससे पहले प्रदेश के बीपीएल, अंत्योदय तथा स्टेट बीपीएल परिवार के प्रति सदस्य को आधा किलो चीनी बांटी जाती थी। लेकिन वर्ष 2017 के बाद चीनी का वितरण केवल अंत्योदय परिवारों को देने के आदेश हुए। राशन डीलरों ने अपने स्टॉक में पड़ी चीनी का वितरण वर्ष 2020 तक किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने चीनी का उठाव नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि सरकारी गोदामों में चीनी का स्टॉक जमा होता गया। इसके बाद वर्ष 2020 में प्रदेश कोविड की चपेट में आ गया।

- **बीकानेर के 4 गोदामों में पड़ी 613 क्विंटल चीनी स्टॉक का फूड डिपार्टमेंट से सैंपल करवाया तो उसकी रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आई**

सरकारी आंकड़े देखें तो वर्ष 2017 में बीपीएल के 22.28, स्टेट बीपीएल के 5.70 तथा अंत्योदय योजना के तहत 6.35 लाख परिवारों को चीनी का वितरण किया जाता था। वर्तमान में राशन व्यवस्था के तहत किसी भी श्रेणी के राशन उपभोक्ता को चीनी और केरोसिन का वितरण नहीं हो रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए की चीनी खराब होने के मामले में रसद विभाग के अधिकारी ख़ौफ़ज़दा है। खाद्य विभाग के मंत्री सुमित गोदारा लगातार राशन वितरण की पारदर्शिता को लेकर गम्भीर हैं। आमजन की शिकायतों के बाद उन्होंने हाल ही में उनकी अनुशंसा पर रसद विभाग में तबादलों का दौर भी शुरू हुआ था। उन्होनें 60 वर्ष से ऊपर और 18 साल से कम उम्र के परिजनों को निशुल्क राशन घर पहुंचाने की व्यवस्था प्रदेश में शुरू की है। बताया जा रहा है कि रसद विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने प्रदेश में राशन की चीनी के खराब होने को गंभीरता से लिया है। उनकी अनुशंसा पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।

नीतू अग्रवाल, मैनेजर, सिविल सप्लाई बीकानेर इनका कहना है कि बीकानेर में 613 क्विंटल चीनी का स्टॉक यहां के 4 सहकारी भंडारों के गोदामों में पड़ा है। मामला काफी पुराना है, चीनी की सैंपलिंग करवाई है। निस्तारण कमेटी के उच्चाधिकारियों से जो भी निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप चीनी का निस्तारण करवाया जाएगा।

माथुरादास माथुर अस्पताल में ब्लॉकेज की सफल रिपेयर एवं बाइपास सर्जरी की

जोधपुर, (कासं)। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के अधीन सबसे बड़े सरकारी अस्पताल माथुरादास माथुर अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग में हृदय के एन्यूरिज्म(विस्फर)एवं ब्लॉकेज की सफल रिपेयर एवं बाईपास सर्जरी की गई।

डॉएसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर डॉ भारती सारास्वत तथा एमडीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ नवीन किशोरिया ने सीटीवीएस टीम को बधाई दी। कॉलेज प्रवक्ता डॉ जयराम रावतानी ने बताया कि यह ऑपरेशन मुख्य मंत्री चिकित्सा योजना के अंतर्गत निशुल्क किया गया। सीटीवीएस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सुभाष बलारा ने बताया कि बाड़मेर निवासी 60 वर्षीय गंगाराम गत एक हफ्ते से छाती में दर्द ,अनियमित धड़कन तथा सांस फूलने की तकलीफ के साथ मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती हुए जहां प्रारंभिक जांचों तथा कार्डियोलॉजी विभागध्यक्ष डॉ रोहित माथुर द्वारा की गई हार्ट की ईको एवं एंजियोग्राफी में हृदय के एन्यूरिज्म एवं बाएं तरफ की मुख्य धमनियों में ब्लॉकेज होने की पुष्टि हुई। मरीज एवं परिजनों को अवगत एवं उनकी सहमति के उपरांत मरीज की हार्ट सर्जरी करने का निर्णय लिया गया।

इस ऑपरेशन में डॉ सुभाष बलारा, सह आचार्य डॉ अभिनव सिंह तथा डॉ देवाराम डॉ अमित ,निश्चेतना विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ राकेश करनावत ,सहआचार्य डॉ भारत शामिल थे । परफ्यूशनिस्ट माधो सिंह व मनोज ,ओटी स्टाफ दिलीप,रेखाराम ,नीलम ,ममता एवं इंचार्ज दिनेश गोस्वामी और आसिफ इकबाल ने अपना योगदान दिया। ऑपरेशन के पश्चात मरीज को सीटीआईसीयू शिफ्ट किया गया जहां डॉ हनुमान ,डॉ अफसा खान स्टाफ हरि सिंह ,नरेश, राजेन्द्र , राहुल और रुपेश ने इलाज प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 9 सितम्बर, 2024

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2081, विशाखा नक्षत्र सायं 6:04 तक, वैधृति योग रात्रि 12:34 तक, कौलव करण प्रात: 8:56 तक, चन्द्रमा दिन 11:29 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–तुला, मंगल–मिथुन, बुध–सिंह, गुरू–वृष, शुक्र–कन्या, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज सूर्य षष्ठि व्रत, बलराम जयन्ती, कार्तिक स्वामी दर्शन, वैधृति पूण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:46 तक, शुभ 9:14 से 10:52 तक, चर 1:57 से 3:30 तक, लाभ–अमृत 3:30 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:14, सूर्यास्त 6:35

मेष

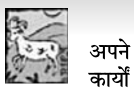

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। पारिवारिक कार्यों में परेशानी हो सकती है।

वृष

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

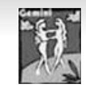

परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

कर्क

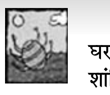

घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या

आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी। आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृश्चिक

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। मन:स्थिति में सुधार होगा।

धनु

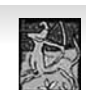

आर्थिक/वित्तिय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। संभावित धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मकर

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।